भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 583

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामले

583. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने मामले दस वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं ;

(ग) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : 15.07.2022 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 2,35,617 हैं और 10 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या 42,374 हैं ।

(ग) और (घ) : 14.07.2022 तक 37 न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद संख्या में से 24 न्यायाधीश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं । 13 रिक्त पदों में से 8 प्रस्तावों की उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई हैं और प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक, सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया हैं । राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित हैं । जब कि प्रत्येक प्रयास शीघ्रता से विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए किया गया है । उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग और उन्नयन के कारण हो रही हैं और न्यायधीशों की पद संख्या में वृद्धि भी एक कारण है ।

******